ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in February 2025

धार एवं बड़वानी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले आर्थिक विकास का आकंलन

रमेश मुझाल्दा, शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा, सिरोही (राजस्थान)
डॉ. सुधा पाण्डेय, आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा, सिरोही (राजस्थान)

प्रस्तावना

धार एवं बड़वानी जिले में कई ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, जिनमें केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कई प्रकार की नवीन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। धार जिले के अंतर्गत कुल 1556 ग्राम आते हैं एवं बड़वानी जिले में 714 ग्राम आते है। धार एवं बड़वानी जिले को मिलाकर 2270 ग्राम आ रहे हैं।

धार एवं बड़वानी जिले में शासकीय योजनाओं का महत्व ज्यादा रहा है, क्योंकि केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कई प्रकार की आर्थिक योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों का विकास दिन प्रतिदिन किया गया है। आज दोनों जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति का मुख्य आधार कृषि है, कृषि के माध्यम से इन लोगों के जीवन में कई प्रकार के बदलाव दिखाई दे रहे है। दोनों जिलों में विकासखण्ड एवं जिले होने के कारण ग्रामीणों में कई प्रकार के बदलाव आर्थिक क्षेत्र में दिखाई दे रहे है। धार एवं बड़वानी जिले में बढ़ती भीड़–भाड़ और गांवों से बढ़ते संपर्क ने बड़े शहरों की प्रशासनिक सीमाओं को बढ़ा दिया है तथा छोटे–मोटे उपशहरों का निर्माण किया है। इससे गांव और शहर के बीच परिवहन और भंडारण की कीमत कम हो जाती है। ये उपशहर गांवों के ही बदलते स्वरूप है। उपषहर/छोटे शहर बड़े शहरों और गांवों के बीच एक मध्यवर्ती श्रृंखला बन गई है। इसने गांवों के विकास और सशक्तिकरण को आगे लाने में मदद की है तथा साथ ही ग्रामीण शहरी पलायन के नकारात्मक प्रभाव को कम कर दिया है।

आर्थिक विकास की बात की जाय तो विकास के बयारों से शहरों की तरह गांवों में विभिन्न तरह के सरकारी और निजी विद्यालयों, अस्पतालों, राष्ट्रीयकृत बैंकों व ग्रामीण बैंकों तथा छोटे–छोटे कारोबारों इत्यादि की स्थापना हुई है। इन सबके निर्माण और काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भूमि और मकान की जरूरत पड़ी । इन चीजों से ग्रामीण में भी अधिक आय और मकान का किराया बढ़ गया है। भूमि कि उपयोगिता, फार्मिंग व्यवस्था एवं श्रम बल की भागीदारी इत्यादि में बदलाव आ चुका है। छोटे स्तर के उद्योग भी स्थापित हुए है। एक शोध के अनुसार 30–40 ग्रामीण युवा वर्ग कृशिगत कार्यों को नहीं करना चाहते है।

शहर के आसपास के ग्रामीण लोगों की आय को बढ़ाने में शहरीय केन्द्र की भूमिका है। शहर के लोगों के खाद्यान्न की भरपाई वहां के किसानों द्वारा की जाती है, जिससे उनकी आय में नगद वृद्धि होती है। यह स्थानीय श्रम बाजार में भी बदलाव लाता है। बेहतर परिवहन से कई मजदूर शहरों में काम कर फिर षाम को घर वापस आ जाते है। धार एवं बड़वानी जिले के आसपास के गांवों को देखा जा सकता है जिसमें अनुत्पादक कहीं जाने वाली महिलाएं मुख्य है। वे शहरों में कई कार्यो जैसे हरी सब्जियां बेचना, गृह कार्य आदि कर नगद पैसों की कमाई भी कर लेती है। इस कमाई से अपने तथा अपने परिवारों की परिवरिश कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती चली जा रही है। शहरों में शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाएं उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा पाती हैं। वैसे ही गांवों की महिलाएं मनरेगा जैसे रोजगारपरक कार्यक्रमों से पैसे कमा रही है। इंटरनेट, मोबाईल तथा टी.वी. के प्रयोग करने से वे अपनी शहरी महिलाओं से तुलना करने लगी है तथा वैसा ही मान–सम्मान पाना चाहती है। अर्थात् गांवों की तरफ नई तकनीकी और आर्थिक विकास शहरों से ही होकर आ रहे है।

धार एवं बड़वानी गांवों से शहरों की तरफ लगातार पलायन हो रहे है। इस पलायन के पीछे चाहे 'पुल' या 'पुश' कारक काम कर रहे हो। लेकिन पलायनवादी सोच व रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। जनगणना 2011 के अनुसार 65 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है तो वहीं शहरी जनसंख्या बढ़ते हुए 35 प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है। पलायनवादी लोग अपनी आय का आधे से अधिक हिस्सा गांवों में भेज देते है तथा अपने परिवार से संपर्क के लिए मोबाईल खरीद कर भेजते है। कई ऐसे लोग हैं जो षहरों में अल्पकालीन कार्य कर मौसमी कार्यो के लिए पुनः गांव लौट आते है। ऐसे व्यक्ति गांवों से शहर–सह–गांव की परम्परा को जारी रखते है। इसका परिणाम यह होता हैं कि इससे ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है साथ ही साथ गांवों के लोगों के रहन–सहन में भी बदलाव आता है। अतः कुछ मायनों में गांवों की दिख रही मिश्रित संस्कृति, रहन–सहन व परम्परा का द्योतक शहर ही है।

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in February 2025

धार एवं बड़वानी जिले में कई प्रकार के ग्रामीण पर्यटन आते है। ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा ने शहरी लोगों व सैलानियों को गांवों की ओर आकर्शित किया है। शहरों से बहुत सारे लोग गांव की ऐतिहासिक इमारतें, रहन–सहन, भोजन तथा हस्तषिल्प इत्यादि देखने जा रहे है। राज्य सरकारों ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई जगहों पर 'टूरिज्म हाट' भी खोल रखे है। इसके माध्यम से गांवों में विभिन्न तरह के आय के स्त्रोत बनते है। यह शहरों से गांवों की तरफ आर्थिक स्थानांतरण का एक जरिया हो सकता है।

गांवों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए शहरी और ग्रामीण स्कूलों के बीच कड़ी का विकास हुआ है जिससे अच्छे अभ्यास एक–दूसरे के बीच बांटे जा रहे है। गांवों में खुल रहे बहुतेरे निजी स्कूलों का नामकरण शहर के प्रसिद्ध स्कूलों के नाम पर या कुछ परिवर्तन कर रखा गया है जो अभिवावकों व बच्चों को अपनी ओर आकर्शित करते है। गांवों में भी शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम अंग्रेजी देखा जा सकता है। शहर–आधारित उद्योग एवं ग्रामीण कृषि उत्पादकता के जुड़ाव ने क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया है। बाजार ज्यादातर शहरी केन्द्रों में अवस्थित होते है। इन बाजारों ने कृषक को व्यावसायिक कृषिगत उत्पाद को उगाने तथा लोगों को फार्म क्रियाकलापों में लाने को प्रोत्साहित किया है। गांवों और छोटे शहरों में देखा जा रहा है कि कई बड़े शहरों के छोटे व्यापारी गांवों में अपना कारोबार फैलाए हुए है। शहरों में प्रयोग होने वाले मषीन निर्मित सामनों (मैन्युफैक्चरिंग गुड्स) ने गांवों के लोगों को प्रयोग करने का आदी बना दिया है। उससे उनके जीवन–स्तर में बड़ा परिवर्तन आया है।

संबंधित साहित्य का पुनर्रावलोकन :–

चेम्बर्स, 1983 ने ग्रामीण विकास को लोगों के एक विशिष्ट समूह, गरीब ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को सक्षम बनाने के लिए एक कार्यनीति के रूप में परिभाषित किया है, ताकि वे अपने और अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी चाहते हैं और जिनकी उन्हें आवश्यकता हैं उससे अधिक प्राप्त कर सकें।

सिंह, 1986 ने ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की तलाश करने वालों में सबसे गरीब लोगों की सहायता करना शामिल है ताकि ग्रामीण विकास के अधिक लाभों की मांग की जा सके और गरीबी को नियंत्रित किया जा सके। इस समूह में छोटे पैमाने के किसान, काश्तकार और भूमिहीन शामिल हैं।

त्रिपाठी, 1988 के अनुसार ग्रामीण विकास गतिविधियों का एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें कृषि वृद्धि, आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढ़ांचे का विकास, ग्राम नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता और संचार आदि शामिल हैं।

तालिका क्रं. 1 शासकीय योजनाओं से लाभ

स.क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	19	63.3
2.	नहीं	11	36.4
	योग	30	100

शासकीय योजनाओं का लाभ लेने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 19 हैं, जिनका प्रतिशत 63.3 है। शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं लेने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 11 हैं, जिनका प्रतिशत 36.4 है।

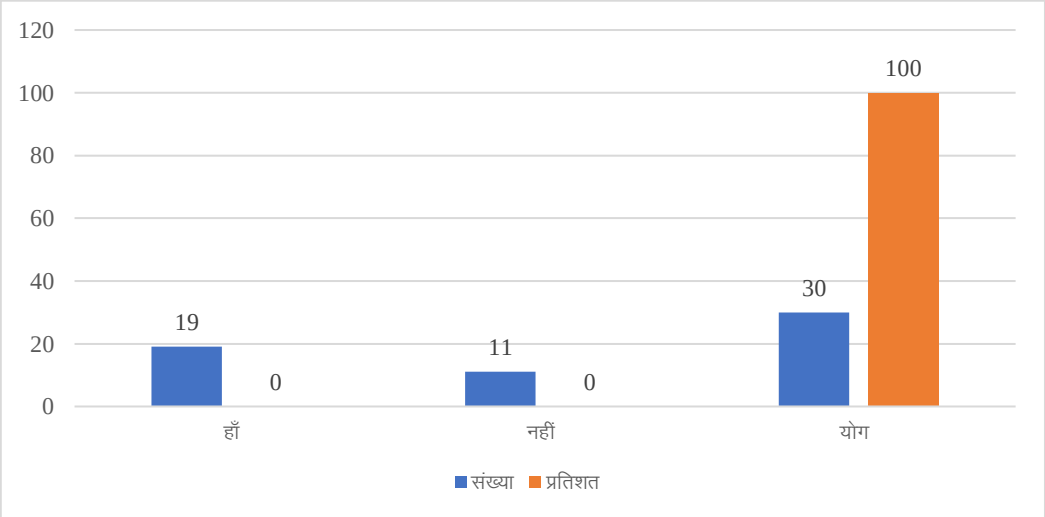

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in February 2025

तालिका क्रं. 2 शासकीय योजनाओं से आर्थिक स्थिति में सुधार

स.क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	18	60
2.	नहीं	12	40
	योग	30	100

शासकीय योजनाओं के उपयोग से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हैं, इस बात का समर्थन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 18 हैं, जिनका प्रतिशत 60 है वहीं इस बात का समर्थन नहीं करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 12 है, जिनका प्रतिशत 40 है।

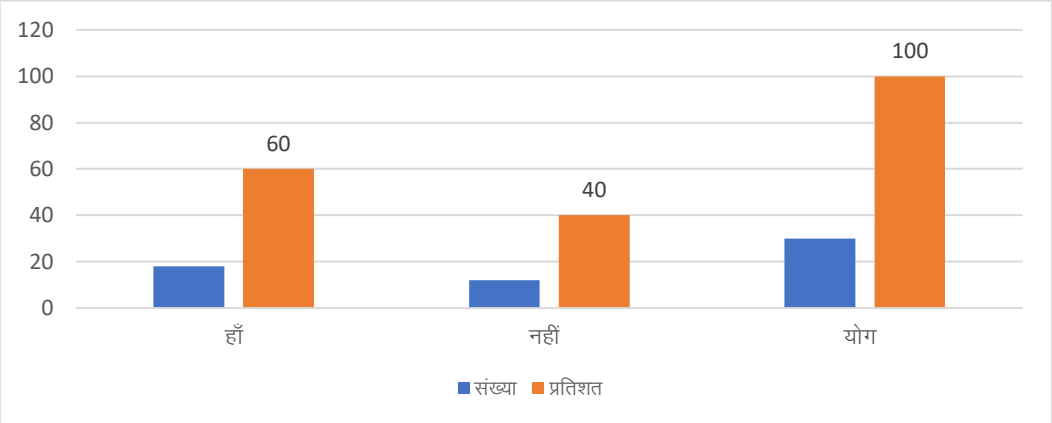

तालिका क्रं. 3 कृषि क्षेत्र के द्वारा शासकीय योजनाओं का लाभ

स.क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	17	56.6
2.	नहीं	13	43.4
	योग	30	100

कृषि क्षेत्र में शासकीय योजनाओं का लाभ उत्तरदाताओं के द्वारा लिया जा रहा हैं, इस बात का समर्थन करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 17 है, जिनका प्रतिशत 56.6 है एवं इस बात को नहीं मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 13 है, जिनका प्रतिशत 43.4 है।

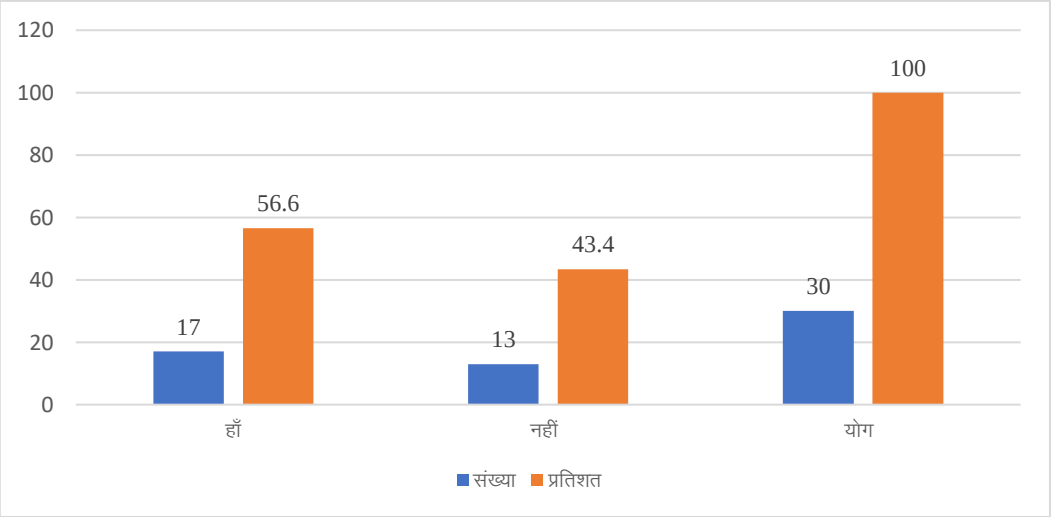

निष्कर्ष :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक मात्रा में कृषि क्षेत्रों में ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए जिससे निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर के ग्रामीण जनों के द्वारा उस योजना का लाभ ले सके।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ग्रामीण स्तर पर उद्योग धन्धों को स्थापित करना चाहिए। हर ग्रामीण क्षेत्र में अनेक प्रकार के उद्योग धन्धे होने से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही

रोजगार उपलब्ध हो सकेगे। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव दिखाई देगा और उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बदलती नजद आयेगी।

- ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं के उपयोग के लिए हर एक सप्ताह में प्रशिक्षण का कार्य किया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण जन उस कार्यक्रम में भाग लेकर संबंधित योजना का उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है और आने वाले समय में इस योजना के माध्यम से किस प्रकार का मिल सकता है आदि की जानकारी नाटक के रूप में भाषण के रूप एवं अन्य माध्यमों के द्वारा लिया जाना चाहिए।
- ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को शासकीय योजनाऐं आसानी से पहुंच सके इसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले युवा वर्ग को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले इसके लिए हर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर उद्योग धन्धे स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके जिससे उनको रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी अन्य शहरों में भटकना नहीं पड़ेगा और लोगों को स्थानीय स्तर पर ही आसानी से रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. ग्रामीण विकास एवं रोजगार अध्याय 12 के अनुसार आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
2. मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ, (2009), "सामाजिक शोध व सांख्यिकी" विवेक प्रकाशन जवाहर
3. नगर, दिल्ली।
4. त्रिवेदी आर.एन. एवं शुक्ला डी.पी. (2009), "रिसर्च मैथ्डोलॉजी" कॉलेज बुक डिपो, 83 तिरपोलिया बाजार, जयपुर पृ 178।
5. जनसंख्या के अंतिम आँकड़े : भारत की जनगणना 2011 निर्देशक जनगणना कार्य
6. निदेशालय मध्यप्रदेश, भोपाल
7. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका : जिला कार्यालय, धार म.प्र. 2016
8. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका : जिला कार्यालय, बड़वानी म.प्र. 2016
9. प्राथमिक स्त्रोत :– धार एवं बड़वानी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षात्कार के आधार पर, 2024